Volume : 3 | Issue : 6 | June 2014 • ISSN No 2277 - 8160

Research Paper Economics

Gramin Berojgri par Manrega Yojna ke Prabhav ka Adhyayan

ग्रामीण बेरोजगारी पर मनरेगा योजना के प्रभाव का अध्ययन
(छ0ग0 राज्य में कोरिया जिले के खड़गवां विकासखण्ड के संदर्भ में)

Ku. RANJNA NEELIMA KACHHAP
Assistant Professor (Economics), Govt. Naveen girls college Baikunthpur, District Korea Chhattishgarh, Sarguja university Ambikapur

Dr. V. M. JURRY
Professor & H.O.D. (Economics), B.C.S. Govt. p.g. College Dhamtari, District Dhamtari Chhattishgarh

ABSTRACT

प्रस्तुत आलेख में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के खड़गवां विकासखण्ड में किस तरह की बेरोजगारी पायी जाती है, बेरोजगारी के क्या कारण हैं, उस पर मनरेगा योजना का क्या प्रभाव पड़ा है। यह जानने का प्रयास किया गया है। जिससे यह बात सामने आयी कि विकासखण्ड के लगभग सभी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इसलिए यहां मुख्य रूप से ग्रामीण बेरोजगारी अर्थात मौसमी बेरोजगारी व छिपी हुई बेरोजगारी ही पायी जाती है। बेरोजगारी के कई कारण हैं पर मुख्य कारण शिक्षा की कमी व पूंजी का अभाव देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना चलने से ग्रामीण बेरोजगारी समाप्त तो नहीं हुई है पर कुछ हद तक कम हुई है। इससे जिन क्षेत्रों में अच्छे से कार्य हुए हैं वहां ग्रामीण बेरोजगारी के साथ–साथ मजदूरों के जीवन के कई पहलू प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिला है। आय में वृद्धि होने के साथ–साथ रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है। कय क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

KEYWORDS : 1. ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी व उसके मुख्य कारणों का अध्ययन करना। 2. ग्रामीण बेरोजगारी पर मनरेगा योजना के प्रभावों का अध्ययन करना।

प्रस्तावना –:

भारत गांवों का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत जनता गावों में निवास करती है। छत्तीसगढ़ की 76.76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कोरिया जिले की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यह जनजातीय बाहुल राज्य है। यहां कुल जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत अनु0ज0जा0 तथा 12.82 प्रतिशत अनु0जातियॉ निवास करती हैं।"1 इसलिए शिक्षित बेरोजगारी के साथ–साथ ग्रामीण बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। बेरोजगारी किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है बल्कि पूरे भारत देश में ही बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गयी है। ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य कारण लोगों में शिक्षा का अभाव है। अशिक्षित या कम पढ़े लिखे होने के कारण उनकी सोच, रहन–सहन व कार्य करने के तरीकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जनवरी 2011 में भारत में बेरोगारी दर 9.4 प्रतिशत पायी गयी। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 10.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 7.3 प्रतिशत थी। 2012 में बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत पायी गयी।

"जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और वह काम करने के लिए शारीरिक दृष्टि से समर्थ भी है, लेकिन अगर उसको कार्य नहीं मिलता जिससे कि वह व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सके तो इस प्रकार की समस्या को बेरोजगारी की समस्या के नाम से जाना जाता है।"2 यही बेरोजगारी कई तरह की समस्याओं को जन्म देती है। बेरोजगार होने के कारण लोग चोरी, डकैती, लूट–मार तथा असामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं। जिससे सामाजिक अशांति फैलती है।

ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने व लोगों को आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से ही सरकार की महत्वकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। "मनरेगा दुनिया का अब तक का ऐसा पहला कानून है जिसमें व्यापक पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार बढ़ाना है। इसका सहायक उद्देश्य उन कार्यों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है जो सूखा, वनों की कटाई तथा मृदा क्षरण जैसे स्थायी गरीबी के कारणों को दूर करते हैं तथा स्थायी विकास को बढ़ावा देते हों।"3 यह योजना बेरोजगारी कम करने में काफी हद तक सहायक भी सिद्ध हुई है।

उद्देश्य –:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी व उसके मुख्य कारणों का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण बेरोजगारी पर मनरेगा योजना के प्रभावों का अध्ययन करना।

पूर्व शोध साहित्य का अध्ययन

1. शैलेन्द्र कुमार नागवंशी (2002–03) (लघु–शोध)

"आदिवासी ग्राम कलरखा (कोण्डागांव) सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण"–एक अध्ययन। इनके अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीणों की कृषि व्यवस्था व उत्पादन पर प्रकाश डालना तथा ग्रामीण बेरोजगारी व उसके स्वरूप का अध्ययन करना साथ ही ग्रामीण आदिवासी जो शोषण के शिकार रहे हैं उन पर प्रकाश डालना आदि है। जिसमें यह पाया गया कि गांव में अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी पायी जाती है। गांव की कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। सिंचाई सुविधाओं

2- A. P. Palanichmy (2011) -
-A study on Mahatma Gandhi National Rural Employment Gauretee Program in Thuinjapuram block Thiruvannamalai district in tamilnadu. इन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर एक अध्ययन किया है – इस अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी पायी जाती है। तथा मौसमी उतार चढ़ाव पाये जाते हैं। अतः मनरेगा इसको दूर करने में कितना सहायक है तथा इसके अंतर्गत कितने श्रमिक कार्यरत हैं, कितने जॉब कार्ड धारी हैं, कितने महिला श्रमिक हैं आदि का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन पद्धति –:

प्रस्तुत आलेख में अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची

उपकरण तथा प्रत्यक्ष अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है। साथ ही द्वितीयक स्त्रोतों का भी सहारा लिया गया है।

अध्ययन का वर्णन व प्राप्त परिणाम

कोरिया जिला जनजातीय बाहुल जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कुल जनसंख्या में 46.18 प्रतिशत अनु0ज0जा0 तथा 8.31 प्रतिशत अनु0 जा0 का है। कोरिया जिले में पांच विकासखण्ड बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, सोनहत तथा जनकपुर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित होती है। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना ही होता है। "2001 की जनगणना के अनुसार कोरिया जिले में मुख्य कार्यशील जनसंख्या कृषक के रूप में 93228, पारिवारिक उद्योग में लगे 2863, खेतिहर मजदूर 19273, अन्य कार्यशील 66473 तथा सीमांत कार्यशील 97989 हैं। कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 47.72 है।"6 क्षेत्र के अवलोकन से पता चलता है कि सभी ग्रामीणों के पास इतनी पर्याप्त जमीन नहीं होती है कि उस पर खेती करके पूरे साल भर के खाने का खर्च निकाला जा सके। लेकिन जितनी भी जमीन होती है उस पर कृषि अवश्य की जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारी ही देखने को मिलती है – जैसे

छिपी बेरोजगारी –:

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। जमीन थोड़ी हो या ज्यादा जब उस जमीन पर घर के सभी सदस्य काम करते हैं, भले ही उस काम में उतने लोगों की आवश्यकता न हो। इस तरह जरूरत से ज्यादा लोग उस कार्य में लगे होते हैं, अर्थात यदि उनमें से कुछ लोगों को अलग कर भी दिया जाय तो कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होती है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है।

मौसमी बेरोजगारी –:

दूसरी तरफ भारत के कई क्षेत्रों की स्थिति अब भी ऐसी है कि उन क्षेत्रों में सिंचाई

सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। कोरिया जिले का खड़गवां विकासखण्ड भी ऐसा ही है। 30 गावों का सर्वे करने पर पता चला कि 2–3 गांवों को छोड़कर शेष गांवों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव पाया गया। जिसके कारण लोग केवल एक फसल पर निर्भर करते हैं। ये फसल भी पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती है। कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण लोगों को खेती संबंधी मजदूरी एक मौसम में ही प्राप्त होती है। अर्थात फसलों की रोपाई और कटाई को छोड़कर बाकी मौसम में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है।

शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारी –:

ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारी भी देखने को मिल रही है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ लोग शिक्षित हो रहे हैं किन्तु उच्च शिक्षा की कमी है। कक्षा 5वीं, 8वीं पढ़ा व्यक्ति भी नौकरी की चाह रखता है और अन्य कार्य नहीं करना चाहता है। जबकि उतनी कम शिक्षा का आज के समय में देखा जाय तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए भी कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण –:

1. शिक्षा की कमी – कोरिया जिले में जनजातियों की संख्या अधिक है। खड़गवां विकासखण्ड के ज्यादातर गांव जंगलों व पहाड़ो की तराइयों में बसे नजर आते हैं। तालिका क0 1 में 300 परिवारों के अध्ययन से पता चलता है कि 42 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं, 30 प्रतिशत प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त किये हैं, 17 प्रतिशत पू0मा0 तथा 10 प्रतिशत 10 वीं 12 वीं फेल हैं। किन्तु उनके बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा की कमी के कारण लोग बेरोजगार हैं।
2. पूंजी का अभाव – बेरोजगारी के कारणों में एक कारण यह भी है कि जनजातीय परिवारों के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण वे जो भी कमाते हैं उसे दो वक्त की रोटी जुटाने में ही खर्च कर देते हैं। उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें या खुद का व्यवसाय चला सकें। चित्र क0 1 से पता चलता है कि 98 प्रतिशत परिवार ने पूंजी का अभाव बताया।
3. मौसमी कृषि –: मौसमी कृषि के कारण भी लोग खेती के दिनों को छोड़कर शेष समय में बेरोजगार होते हैं। चित्र क्रमांक 1 में 90 प्रतिशत परिवारों ने इसे भी एक कारण बताया।
4. मानसून की अनियमितता –: ग्रामीण जनता कृषि पर निर्भर होती है, और कृषि मानसून पर निर्भर होती है। तालिका क0 2 में 90 प्रतिशत परिवारों ने सिंचाई सुविधाओं का अभाव बताया। यदि मानसून अच्छा तो उत्पादन अच्छा और मानसून सही न होने से फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यह भी बेरोजगारी का एक कारण है।
5. भूमि का उप–विभाजन –: भूमि का उप विभाजन भी बेरोजगारी का एक कारण है। भूमि को भाई–भाई में, बाप–बेटे में बांटते–बांटते इतने छोटे–छोटे टुकड़े कर दिये गये हैं कि कृषि उत्पादन ढंग से नहीं हो पाता है।
6. लघु व कुटीर उद्योगों का पतन :– पहले जिन परिवारों के लिए लघु व कुटीर उद्योग आय प्राप्त करने का जरिया था उनके पतन के कारण लोग बेरोजगार हो गये।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को कार्य कम व ज्यादा आराम का पसंद होना – कुछ ग्रामीण ऐसे भी देखने को मिले जैसे कुछ काम कर लिए उसकी मजदूरी मिल जाती है। तो अन्य काम मिलने पर उसे प्राथमिकता नहीं देते हैं भले ही वो क्यों न घर में आराम कर रहे हों। ऐसी स्थिति भी बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि करते हैं।
8. दोषपूर्ण विचार पद्धति – ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद नौकरी चाहते हैं। वे कृषि कार्य भी नहीं करना चाहते और स्वयं के व्यवसाय के लिए उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है। यह भी बेरोजगारी का एक कारण है।
9. कृषि के क्षेत्र में पूंजी प्रधान तकनीकों का अभाव – ग्रामीण कृषि करते भी हैं तो पुराने तकनीक का प्रयोग करते हैं जिससे उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता। क्योंकि अच्छे बीज, खाद व अन्य चीजें खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं।
10. प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव – ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर श्रमिक अप्रशिक्षित होते हैं। अप्रशिक्षित होने के कारण बेरोजगारी उनमें अधिक पायी जाती है।
11. जनसंख्या वृद्धि – ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का एक कारण है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और कमाने वाले कम होते हैं। अर्थात आधे लोग कार्य करना नहीं चाहते जो बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है।

बेरोजगारी का लोगों के जीवन पर प्रभाव

1. बेरोजगार होने के कारण लोगों में ऋणग्रस्तता पायी जाती है।
2. स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता है।
3. पूंजी व रोजगार के अभाव के कारण रहन–सहन का स्तर निम्न पाया जाता है।
4. रहन–सहन का स्तर निम्न होने के कारण लोगों का उपभोग व व्यय करने की क्षमता कम होती है।
5. बेरोजगारी के कारण कई सामाजिक कुरीतियां आये दिन देखने व सुनने को मिलती है।
6. बेरोजगारी आर्थिक विकास में भी बाधक होती है।

बेरोजगारी पर मनरेगा योजना का प्रभाव –

ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय परिवारों पर मनरेगा योजना के प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण, कृषि के मौसम को छोड़कर बाकी समय बेरोजगार हो जाते हैं। उनको जीविका चलाने के लिए दूसरे गांव, दूसरे शहर काम के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मनरेगा उनकी बेरोजगारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

1. रोजगार की स्थिति – तालिका क0 3 में रोजगार की स्थिति के संबंध में 300 परिवारों से पूछने पर कि आपके रोजगार की स्थिति क्या है? 100 प्रतिशत ने कहा कि मौसमी रोजगार है।
2. बेरोजगारी पर प्रभाव –तालिका क्रमांक 4 में 98 प्रतिशत ने कहा कि मनरेगा योजना चलने से बेरोजगारी कम हुई है। किन्तु 02 प्रतिशत ने कहा कि बेरोजगारी कम नहीं हुई है।
3. रोजी रोटी पर प्रभाव – मनरेगा योजना ग्रामीण मजदूरों के जीवन में दो वक्त की रोटी जुटाने में अहम भूमिका निभाती है।
4. आय पर प्रभाव – मजदूरी बढ़ने से निश्चित ही आय में वृद्धि हुई है।
5. ऋण चुकाने में सहायक – ग्रामीण मजदूरों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे ऋण भी लेते हैं। 30 गांवों के सर्वे से इस बात का पता चला कि 40 प्रतिशत मजदूर मनरेगा की मजदूरी से ऋण अदा कर पाते हैं।
6. उन्नत किस्म के खाद व बीज का प्रयोग – 50 प्रतिशत मजदूरों ने कहा कि मनरेगा से जो मजदूरी प्राप्त होती है उससे धान के बीज वगैरह खरीद पाते हैं। पहले उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है।
7. कार्यक्षमता में वृद्धि – मनरेगा से जो मजदूरी प्राप्त होती है उससे मजदूरों के लेन–देन करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अनाज के रूप में ही मजदूरी प्राप्त होती थी, जिससे लेन देन की क्षमता कम होती थी।
8. रहन–सहन के स्तर में सुधार – कार्यक्षमता बढ़ने से अब लोगों के रहन–सहन में भी बदलाव आया है।
9. अब लोगों को केवल फसल बोने व काटने के समय ही रोजगार मिलता है ऐसा नहीं कहा जा सकता बाकी समय वे मनरेगा में कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं।

निष्कर्ष–:

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता कृषि पर निर्भर होती है। तथा ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत मौसमी बेरोजगारी व छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है। इस बेरोजगारी पर मनरेगा योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिला है, उनकी बेरोजगारी कम हुई है। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। आय बढ़ने से लोगों के रहन सहन के स्तर में भी सुधार हुआ है।

सुझाव –:

1. सिंचाई सुविधाओं का विकास –: ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जिससे लोग कृषि पर ध्यान दे सकें। सिंचाई सुविधा होने से सभी मौसम में वे कुछ न कुछ फसल लगा सकते हैं।
2. लघु व कुटीर उद्योगों का विकास – लघु व कुटीर उद्योगों के विकास करने की जरूरत है। जिससे लोग घर में जो भी सामान बना सकते हैं उसका निर्माण अधिक संख्या में करके आत्मनिर्भर बन सकें। जैसे– बांस के सामान, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन व खिलौने आदि।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का विकास – ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी व छिपी हुई बेरोजगारी पायी जाती है इसलिए कृषि के साथ–साथ मुर्गीपालन, पशुपालन जैसे कार्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
4. गावों के विकास पर बढ़ावा देने की जरूरत – गॉव को शहर नहीं पर शहर जैसी सुविधायें प्रदान की जाय जिससे लोग वहां रहने के लिए उचित वातावरण पा सकें।
5. सामाजिक वातावरण में परिवर्तन की आवश्यकता– ग्रामीणों में यह भावना जागृत करने की आवश्यकता है कि घर में बैठे रहने से अच्छा कुछ न कुछ काम किया जाय जिससे अधिक आय की प्राप्ति हो सकेगी।
6. प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार – प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाय जिससे लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार में लग सकें व बेरोजगारी कम करने में सहयोग दे सकें ।
7. लोगों को रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक दिया जाय जिससे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसके लिए योजना प्रचार–प्रसार कर्मियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
8. मजदूरी की विलंबता को कम करने की जरूरत– ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कार्य करके अपना गुजारा करते हैं यदि उन्हें पैसे न मिले तो रोजगार मिलने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि उन्हें तो दिनभर काम किये शाम को पैसे की जरूरत होती है।
9. कृषि विकास कार्यों को बढ़ावा देने की जरूरत जिससे लोग कृषि कार्य को अधिक करें व उत्पादन में वृद्धि लायें।
10. मनरेगा में ऐसे कार्यों को शामिल करने की जरूरत है जो लोगों को स्थायी रूप

से रोजगार दे सके। जैसे– कृषि योग्य भूमि का विकास, कृषि प्रणाली में सुधार आदि।

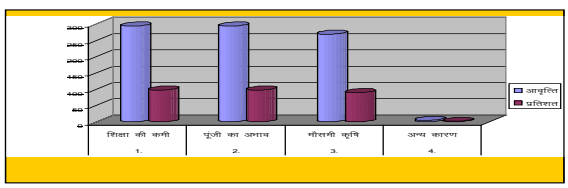
11. पर्यटन स्थलों के विकास संबंधी कार्यों को भी मनरेगा में शामिल किया जा सकता है।

तालिका कमांक 1
उत्तरदाताओं की शिक्षा

शिक्षा का स्तर	अशिक्षित	प्राथमिक	पू0मा0	हाई स्कूल	हायर सेके0	स्नात0	साक्षर	योग
आवृत्ति	128	91	53	18	7	01	02	300
प्रतिशत	42.7	30.3	17.7	6	2.3	0.3	0.7	100

स्त्रोत – प्राथमिक आंकड़े

रेखाचित्र कमांक 1
बेरोजगारी के कारण



स्त्रोत – प्राथमिक आंकड़े

तालिका क0 2
सिंचाई सुविधा संबंधी जानकारी

कमांक	सिंचाई सुविधा	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सुविधा है	30	10
2	नहीं है	270	90
	योग	300	100

स्त्रोत – प्राथमिक आंकड़े

तालिका कमांक 3
रोजगार की स्थिति

रोजगार की स्थिति	बेरोजगार	व र्भिर रोजगार	मौसमी रोजगार	योग
आवृत्ति	–	–	300	300
प्रतिशत	–	–	100	100

स्त्रोत – प्राथमिक आंकड़े

तालिका कमांक 4
बेरोजगारी पर प्रभाव

कमांक	बेरोजगारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कम हुई	295	98
2	नहीं हुई	05	02
	योग	300	100

स्त्रोत – प्राथमिक आंकड़े

REFERENCES

1. जनगणना 2011 के आंकड़े। 2. जैन, किरण, (2013) नवीन संस्करण, अर्थशास्त्र–1, इन्टरनेशनल बुक सेन्टर नई दिल्ली, पेज नं0–495। 3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (नरेगा), वार्षिक रिपोर्ट अप्रैल 2008– मार्च 2009, पेज नं0 5–6। 4. नागवंशी, शैलेन्द्र कुमार (2002–03) (लघु–शोध) "आदिवासी ग्राम कलरखा (कोण्डागांव) सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण" –एक अध्ययन। 5. Planichamy, A. P. (2011): A Study on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (MGNREGP) in Thuinjapuram block Thk-ruvannamalai district in Tamilnadu: International Multidisciplinary Research Journal, vol. 1, no. 3, page no. 37-46. | 6. जिला सांख्यिकी पुस्तिका (वर्ष 2012) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, कोरिया छ0ग0। 7. मिश्रा, सी0एस0 एवं भारद्वाज, अर्थशास्त्र प्रथम वर्ष, नवीन संस्करण, राम प्रसाद एण्ड संस पेज नं0 294–95। 8. http//www.yourarticlelibrary.com./unemployment/rural india. | 9. अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक स्त्रोत।